

10.05.2024

प्रेस विज्ञप्ति
Press Release

बीमा वितरक मंथन
Bima Vitarak Manthan

- बीमा मध्यवर्तियों के साथ अपने ढंग का पहला विचार-विमर्श
- a first of its kind interaction with Insurance Intermediaries

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) भारतीय बीमा क्षेत्र में रूपांतरकारी सुधारों का नेतृत्व करते हुए अग्रस्थान पर है, यह सब व्यापक वित्तीय संरक्षण और सुरक्षा देते हुए प्रत्येक व्यक्ति तक बीमा पहुँचाने की "2047 तक सबके लिए बीमा" की उसकी बृहत्तर परिदृष्टि के भाग के रूप में है।

बीमाकर्ताओं के लिए लागू विनियामक ढाँचे को समाविष्ट करते हुए किये गये हाल के पालिसीधारक केन्द्रित विकासात्मक सुधारों का अनुसरण करते हुए इसी प्रकार के सुधार बीमा मध्यस्थता के परिदृश्य में प्रगति पर हैं।

इस दिशा में आईआरडीएआई ने एक ऐतिहासिक अपने ढंग के दो-दिवसीय विचार-विमर्श "**बीमा वितरक मंथन**" का संयोजन 9 और 10 मई 2024 को हैदराबाद स्थित अपने प्रधान कार्यालय में किया। इस कार्यक्रम में मुख्य मध्यवर्ती एकसाथ सम्मिलित हुए जिनमें दलाल, कारपोरेट एजेंट (बैंक, एनबीएफसी, अन्य) तथा बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) शामिल हैं जिन्होंने देश में बीमा वितरण के भविष्य के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया।

दो दिन के इस कार्यक्रम के दौरान, सहभागियों ने वितरण के परिदृश्य में बहुपक्षीय सुधारों के संचालन पर केन्द्रित रचनात्मक चर्चाएँ कीं। आईआरडीएआई ने समाज के सभी खंडों के लिए बीमा तक अधिकाधिक पहुँच को सुसाध्य बनाने में मध्यवर्तियों की भूमिका में वृद्धि करते हुए, प्रभावी ढंग से मध्यवर्तियों के परिचालनों हेतु सिद्धांत-आधारित विनियम प्रारंभ करने की अपनी परिदृष्टि प्रकट की। अध्यक्ष, आईआरडीएआई ने एक बीमा पारिस्थितिक तंत्र (ईकोसिस्टम) निर्मित करने पर बल दिया, जो "**शून्य संघर्ष, शून्य कष्टप्रद अंश और शून्य शिकायतों**" वाले परिवेश की दिशा में अग्रसर होनेवाले पालिसीधारकों की आवश्यकताओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

बीमा को व्यापक रूप से उपलब्ध, आसानी से पहुँच-योग्य और वहनीय बनाने पर संकेन्द्रित रणनीतियों ने प्रमुख स्थान लिया। बीमा मध्यवर्तियों द्वारा संभावित ग्राहकों और पालिसीधारकों तक उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं का आकलन करने के लिए पहुँचने; तथा विभिन्न आयु समूहों, आय समूहों, व्यवसाय समूहों, लिंग और क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादों के तौर पर जनसाधारण की वैविध्यपूर्ण आवश्यकताओं के अनुरूप बीमा उत्पाद बनाने के लिए बीमाकर्ताओं के साथ भागीदारी करने पर बल दिया गया। स्वत्वाधिकार बीमा और जामिन बीमा जैसे नये उत्पादों पर भी उनके उद्ग्रहण को बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष रूप से बल दिया गया।

एक प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था के होने के साथ ही, अपविक्रय और जबरन विक्रय का समाधान करने के लिए उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। उद्योग की धारणीय वृद्धि हेतु विक्रय बल के लिए निरंतर प्रशिक्षण और वैश्विक बीमा परिदृश्य से सर्वोत्तम प्रथाओं के अंगीकरण की अत्यावश्यक होने के रूप में पहचान की गई।

इस बात पर जोर दिया गया कि प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए वितरण माध्यमों की तत्परता वितरण के क्षेत्र में एक विस्फोट-सा ला देगा जो पालिसीधारकों को लाभ पहुँचाते हुए वितरण की लागतों में कमी के रूप में परिणत हो सकेगा। बीमा को अंतिम गंतव्य तक ले जाने में प्रस्तावित ई-बाजार स्थान – बीमा सुगम का उन्नयन करने के संबंध में विस्तृत चर्चाएँ की गईं।

बीमा वितरक मंथन एक आवधिक अधिवेशन होगा जो विभिन्न मध्यवर्तियों के साथ निरंतर संबद्धता के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जहाँ सार्थक विचार-विमर्श, अंतर्दृष्टियों की साझेदारी और नवोन्मेष कार्यनीतियों और सहयोग का अन्वेषण किया जाएगा।

उक्त फोरम का समापन एक उच्च संकल्प के साथ हुआ जहाँ सभी सहभागियों ने 2047 तक सबके लिए बीमा प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के लिए आशा एवं प्रतिबद्धता व्यक्त की।

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) is at the forefront of spearheading transformative reforms in the Indian insurance sector, all as part of its larger vision of "Insurance for All by 2047" aiming to take insurance to each and every Individual to provide them comprehensive financial protection and security.

Following the recent policyholder centric developmental reforms covering the regulatory framework applicable to insurers similar reforms are underway in the insurance intermediation landscape.

Towards this, IRDAI convened a landmark first-of-a-kind two-day interactions "**Bima Vitarak Manthan**" on May 9th and 10th, 2024 at its head office in Hyderabad. The event brought together key intermediaries, including brokers, corporate agents (Banks, NBFCs, Others) and Insurance Marketing Firms (IMFs) for extensive deliberations on the future of insurance distribution in the country.

Over the course of two-days, participants engaged in constructive discussions centered on driving multi-faceted reforms in the distribution landscape. IRDAI unveiled its vision of instituting principle-based regulations for the operations of intermediaries effectively, enhancing their role in facilitating greater access to insurance for all segments of society. The Chairman, IRDAI emphasized on creating an insurance

ecosystem which is highly sensitive to the needs of the policyholders propelling towards “**Zero Friction, Zero Pain-points and Zero Complaints**” environment.

Focussed strategies to make insurance widely available, easily accessible and affordable took the centre stage. Emphasis was laid on insurance intermediaries reaching out to the prospects and the policyholders to assess their needs and requirements; and partner with insurers to bring about insurance products tailored to the diverse needs of the population in terms of various age groups, income groups, occupational groups, gender and region-specific products. New products such as Title Insurance and Surety Insurance were also highlighted, with the intention of increasing their uptake.

Measures to address mis-selling and force selling were deliberated along with having an effective grievance redressal mechanism in place. Continuous training for sales force and the adoption of best practices from the global insurance landscape were recognized as vital for the sustained growth of the industry.

It was highlighted that the readiness of distribution channels to embrace technology could bring about explosion in the distribution space which can result in reduction of distribution costs benefiting the policyholders. Detailed discussions were held on leveraging proposed insurance e-marketplace – Bima Sugam in taking the insurance to the last mile.

Bima Vitarak Manthan would be a periodic meeting serving as a platform for continuous engagement with various intermediaries, having meaningful interaction, sharing of insights and exploring innovative strategies and collaboration.

The forum concluded on a high note, with all participants expressing optimism and a commitment to work towards the shared goal of achieving Insurance for All by 2047.

.....